349 दर्ज किया गया गुरुवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स। फरीदाबाद में यह 360, गाजियाबाद में 359, ग्रेटर नोएडा में 370, गुरुग्राम में 290 और नोएडा में यह 370 रहा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 27 दिसंबर 2019

राजघाट से दौड़ीं 100 नई अल्ट्रा मॉडर्न बसें

सुरक्षित सफर ▶ बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट, पैनिक बटन समेत सभी आधुनिकतम सुविधाएं हैं उपलब्ध

राजघाट क्लस्टर डिपो से सीएम ने दिखाई हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को राजघाट क्लस्टर डिपो से 100 नई अल्ट्रा मॉडर्न बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें दिल्ली के 12 रूटों पर संचालित की जाएंगी। इन बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे एवं जीपीएस समेत सभी आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। केजरीवाल ने कहा कि पिछले चार माह में बेड़े में अब 529 नई बसें शामिल हो गई हैं। इससे दिल्ली की सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बहुत मदद मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 100 और बसों को डीटीसी के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। दिल्ली के निवासियों को सरकार की तरफ से हर सप्ताह खुशखबरी मिल रही है। अगले तीन-चार महीने में और बसें आने वाली हैं। अब लोगों को बस की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। हमारा मकसद दिल्ली की यातायात व्यवस्था को बहुत ही आधुनिक बनाना है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि आज हमें 100 नई अल्ट्रा मॉडर्न बसें मिली हैं। नई बसों में तीन सीसीटीवी कैमरे हैं। हर वैकल्पिक सीट पर एक पैनिक बटन है और अगर एक पैनिक बटन दबाया जाता है तो एक बड़ा हूटर कमांड सेंटर को सक्रिय करेगा। दिल्ली की हर बस में मार्शल हैं। दिल्ली को नियमित रूप से नई बसें मिलती रहेंगी।

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की ओर से 300 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। ये 1,000 क्लस्टर ई-बसों के अतिरिक्त होंगी, जिन्हें पहले से ही मौजूदा बेड़े में जोड़ा जाना तय है। टेंडर प्रक्रिया जारी है। 1,000 लो-फ्लोर, वातानुकूलित, सीएनजी-रन क्लस्टर बसों के लिए वित्तीय बोली भी खोली गई है। 2019-20 के लिए दिल्ली सरकार के बजट के अनुसार इस वर्ष लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता सहित विभिन्न कारणों से ई-बस खरीद परियोजना में एक वर्ष से अधिक की देरी हुई। इससे पहले दिल्ली सरकार ने इस साल 2 मार्च को 385 पूर्ण-इलेक्ट्रिक बसों के पहले बेड़े के लिए निविदाओं को मंजूरी दी थी। निविदाएं 10 मार्च को मंगाई गई थीं, लेकिन मतदान के कारण प्रक्रिया बाधित हो गई थी। अब प्रक्रिया चल रही है।

राजघाट कलस्टर बस डिपो से नई बसों के शुभारंभ से पूर्व पैनिक बटन की जांच करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। साथ में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (दाएं)। जागरण

महिपालपुर में किया भूमिगत जलाशय का उद्घाटन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ मुख्यमंत्री बोले, एक लाख से अधिक परिवारों को होगा लाभ

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिपालपुर में 60 लाख लीटर क्षमता के नवनिर्मित भूमिगत जलाशय (यूजीआर) का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके चालू हो जाने से आसपास के इलाकों में रह रहे एक लाख से अधिक परिवारों को पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड ने हैदरपुर प्लांट से 12 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर यहां तक पानी पहुंचाया है। 15 करोड़ रुपये की लागत से बने इस भूमिगत जलाशय से महिपालपुर एक्सटेंशन, रंगपुरी गांव, रंगपुरी एक्टेंशन व वसंत कुंज एंक्लेव समेत कई अन्य इलाके के लोग लाभांवित होंगे।

मुख्यमंत्री ने महिपालपुर में भूमिगत जलाशय का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इलाके के निवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस इलाके में पानी की बहुत ज्यादा समस्या रहा करती थी। अब यहां पानी की समस्या का निवारण हो जाएगा। यहां तक पानी पहुंचाने में बहुत सारी अड़चनें आईं। हम सभी अड़चनों को दूर करने के बाद इसे चालू कर रहे हैं। अभी इसकी नई-नई पाइपलाइन है। इसलिए अभी 10 से 15 दिनों तक कुछ परेशानी होगी। इसके बाद ठीक से पानी आने लगेगा। वसंत कुंज एंक्लेव की भी कुछ समस्या थी। उसको भी ठीक कर दिया। अब इसके जरिये वसंत कुंज एंक्लेव में भी पानी पहुंच जाएगा। पांच साल से हमारी सरकार की यही कोशिश रही है कि दिल्ली के कोने-कोने में पानी की लाइन बिछा दी जाए। अगले एक से डेढ़ साल में पूरी दिल्ली में हर घर के अंदर टोंटी से पानी आ जाएगा।

दिल्ली विधानसभा चुनाव का कभी भी हो सकता है एलान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ समीक्षा बैठक में ज्यादातर तैयारियों को लेकर संतुष्ट दिखा आयोग

▶ कम मतदान वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश

चुनाव आयोग ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा बैठक की। आयोग ज्यादातर तैयारियों से संतुष्ट दिखा। हालांकि इस बीच कम मतदान वाले क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। वहीं, ऐसे क्षेत्रों की खासतौर से पहचान करने और उपयुक्त उपाय करने को कहा गया जहां मतदाता निष्पक्ष मतदान न होने को लेकर आशंकित हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों का एलान अब कभी भी हो सकता है। दिल्ली की मौजूदा सरकार का कार्यकाल फरवरी 2020 में खत्म हो रहा है और चुनाव इससे पहले होने हैं।

चुनाव आयोग ने इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली के पुलिस आयुक्त के साथ एक अलग से भी बैठक की। दिल्ली के विशेष आयुक्त प्रवीर रंजन ने कानून-व्यवस्था को लेकर प्रजेंटेशन दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ इस दौरान चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्र भी मौजूद रहे। बैठक में आयोग ने चुनाव से जुड़े सभी बिंदुओं पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से एक-एक कर जानकारी ली। साथ ही बैठक में मौजूद अधिकारियों से भी सवाल-जबाव किए। आयोग ने इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट के प्रशिक्षण से जुड़े अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजनों और बुर्जुगों को मतदान केंद्र तक लाने और छोड़ने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर वोटरों के लिए सभी जरूरी जनसुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। आयोग ने इस दौरान शिकायतों के लिए तैयार किए गए एप (एप्लीकेशन) की जानकारी भी ली। साथ ही निर्देश दिया कि एप पर आने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

इस अहम बैठक में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, दिल्ली छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि मौजूद थे।

न्यूज गैलरी

प्रत्येक जिले में एसआइटी की नहीं है जरूरत

नई दिल्ली : एक याचिका के जवाब में दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि यौन शोषण के मामलों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में विशेष जांच दल (एसआइटी) की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों पर वरिष्ठ अधिकारी जांच पूरी होने तक नजर रखते हैं। एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई थी कि यौन शोषण के मामलों के तेजी से निपटारे के लिए हर जिले में एसआइटी बनाई जाए। दिल्ली पुलिस ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा है कि यौन अपराधों की गंभीरता को देखते हुए कुशल और समयबद्ध तरीके से जांच की जाती है। विशेष पुलिस आयुक्त के अधीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है। इसके बाद निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों की एफआइआर दर्ज करने के समय से ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी नजर रखेंगे। (जासं)

विस चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित की स्क्रीनिंग कमेटी

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) ने गुरुवार शाम स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा कर दी। यही कमेटी दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देगी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति से गठित की गई इस कमेटी का अध्यक्ष वरिष्ठ नेता राजीव सातव को बनाया गया है। वीरेंद्र सिंह राठौर एवं चल्ला वेम्शी चंद रेड्डी को सदस्य रखा गया है। कमेटी में दिल्ली से पार्टी प्रभारी पीसी चाको, सह प्रभारी कुलजीत सिंह नागरा और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा को शामिल किया गया है। (जासं)

साफ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, अपनी दिल्ली अभियान शुरू

नई दिल्ली : दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन और समाज कल्याण मंत्री ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सचिवालय में साफ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, अपनी दिल्ली अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही एक थीम गीत भी लांच किया गया। इस अवसर पर शहरी विकास विभाग की प्रधान सचिव मनीषा सक्सेना सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अभियान के तहत दिल्ली को संवारने और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। (जासं)

दागदार कुंडली वाले इंस्पेक्टर नहीं बन सकेंगे एसीपी

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

▶ पुलिस मुख्यालय ने जिले और यूनिटों के डीसीपी से मांगी जानकारी

दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टरों को पदोन्नति देकर सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 93 इंस्पेक्टरों की सर्विस कुंडली खंगाली जा रही है। इनमें से जिनके खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत पर प्रारंभिक जांच, विभागीय जांच, आपराधिक मामले व विजिलेंस जांच आदि हुई है तो उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। मुख्यालय ने गत 24 दिसंबर को सभी 15 जिले व यूनिटों के डीसीपी को पत्र भेजकर इस संबंध में 30 दिसंबर तक जानकारी देने को कहा है। निर्धारित तिथि तक किसी इंस्पेक्टर के बारे में मुख्यालय को जवाब नहीं मिलेगा तो इसके लिए इंस्पेक्टर खुद भी जिम्मेदार होंगे।

दिल्ली पुलिस के विभिन्न जिले व यूनिटों में तैनात 12 दानिप्स एसीपी को गत दिनों उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पदोन्नत कर एडिशनल डीसीपी बना दिया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस में एसीपी के 12 पद पद खाली हो गए हैं। वहीं विभिन्न थानों व यूनिटों में तैनात 93 इंस्पेक्टरों की पदोन्नति विचाराधीन है। उन्हें वेतन तो एसीपी ग्रेड का मिल रहा है, लेकिन उन्हें एसीपी का रैंक नहीं मिल पाया है। इनमें कुछ इंस्पेक्टर तो ऐसे हैं, जो लगातार सात बार थानाध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और कई ऐसे हैं जिन्हें एक या दो बार ही थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक के सफर में बहुत अधिकारी होते हैं, जिन पर कोई दाग न लगा हो। इसलिए मुख्यालय ने जिले व यूनिटों में तैनात इंस्पेक्टरों के बारे में डीसीपी से वर्तमान स्टेटस के बारे में जानकारी मांगी है। यह जानकारी भविष्य में पदोन्नति को लेकर होने वाली बैठक में रखी जा सकेगी। सूत्रों के मुताबिक इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सब डिवीजन, स्पेशल सेल व क्राइम जैसी यूनिटों में इंस्पेक्टरों को भेजा जाएगा। इसे लेकर इंस्पेक्टरों में खलबली है। सभी अपने-अपने अधिकारियों से मिलकर रिपोर्ट दुरुस्त करने में जुटे गए हैं। सूत्र बताते हैं कि 93 इंस्पेक्टरों की सूची लंबी है, इनमें उन्हीं इंस्पेक्टरों को पदोन्नत किया जाएगा, जिनपर कभी दाग नहीं लगा है।

निर्भया के दोषी मुकेश ने जेल प्रशासन को नोटिस का नहीं दिया जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए चार दोषियों को जेल प्रशासन की ओर से जारी नोटिस का उत्तर देने की समय सीमा गुरुवार को समाप्त हो गई। सात दिनों में जेल प्रशासन को सिर्फ दोषी अक्षय, विनय और पवन की ओर से ही जवाब मिला, जबकि मुकेश ने जवाब नहीं दिया है। जेल के अतिरिक्त महानिरीक्षक राजकुमार ने बताया कि इस मामले में जेल प्रशासन की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट को वस्तुस्थिति की जानकारी दी जाएगी। कोर्ट का जो निर्देश आएगा, उसका पालन किया जाएगा।

जेल प्रशासन की ओर से चारों दोषियों को जारी किए गए नोटिस में सात दिन का वक्त दिया गया था। इस नोटिस के जवाब में अक्षय, विनय व पवन की ओर से जेल प्रशासन को बताया गया कि अभी उनके पास दया याचिका से पूर्व क्यूरेटिव याचिका दायर करने का विकल्प मौजूद है। क्यूरेटिव याचिका दायर करने के बाद जो नतीजे आएंगे, उसके आधार पर आगे क्या करना है, यह तय करेंगे। जेल प्रशासन के अनुसार, सात जनवरी को इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है।

'समय निकाल कर शाह आएं, मैं उन्हें सरकारी स्कूल दिखाता हूं'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ अमित शाह के बयान पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया पलटवार

▶ बोले, आपको दिल्ली में कुछ ऐसे लोगों से मिला देते हैं, जिनकी बिजली फ्री हुई है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोप पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरी गृहमंत्री से विनती है कि वह दो-चार दिन का समय निकालें तो मैं उन्हें दिल्ली सरकार के स्कूल और एमसीडी के स्कूल दिखा देता हूं।

शाह ने एक कार्यक्रम में आरोप लगाया कि केजरीवाल सिर्फ प्रचार करते हैं और दूसरों के कराए काम पर ठप्पा लगाते हैं। इस पर सिसोदिया ने कहा कि मेरी गृहमंत्री से विनती है कि वह दो-चार दिन का समय निकालें। अगर चुनाव से फ्री हो गए हों तो दिल्ली चुनाव से पहले आएं तो मैं उन्हें दिल्ली सरकार के स्कूल दिखा देता हूं, एमसीडी के स्कूल दिखा देता हूं, कुछ मोहल्ला क्लीनिक दिखा देता हूं, कुछ सरकारी अस्पताल दिखा देता हूं। साथ तो चलिए हम आपको दिल्ली में कुछ ऐसे लोगों से मिला देते हैं, जिनकी बिजली फ्री हुई है। मेरी विनती है दिल्ली की ओर चलिए तो सही। दिल्ली की तरफ ध्यान तो दीजिए। प्रवेश वर्मा पर तंज करते हुए कहा कि पहले वे बता तो दें कि सीएम पद का उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को बना रहे हैं या मनोज तिवारी को।

केजरीवाल का काम मोदी के नाम पर गिनाने में जुटे शाह : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि रामलीला मैदान से पड़ी डांट के कारण मोदी को खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल का काम मोदी के नाम पर गिनाने पर जुट गए हैं। संजय सिंह ने ट्वीट किया कि चार दिन पहले मोदी जी ने रामलीला मैदान से अमित शाह को डांट लगाई तो वे मोदी जी को खुश करने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल का काम मोदी के नाम पर गिनाने में जुट गए हैं। वहीं एक अन्य ट्वीट में संजय सिंह ने कहा कि 2019 का सबसे बड़ा मजाक। अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के कामों में अड़ंगा लगा रहे हैं।

डीएसजीपीसी सरकारी योजनाओं की जानकारी अल्पसंख्यकों को देगी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इसके लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) ने कई नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणजीत कौर ने नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाने का निर्देश दिया।

कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन जसविंदर सिंह जौली ने कहा कि अल्पसंख्यक बच्चों के लिए भी कई सरकारी योजनाएं हैं, जिसके तहत स्कूल फीस माफी के साथ छात्रवृत्ति और पाठ्य सामग्री भी दी जाती है। इसका लाभ सिख बच्चों को मिले, इसके लिए नोडल अधिकारी लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें आवेदन करने में भी मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि पहली से 12वीं कक्षा तक 50 फीसद से ज्यादा अंक हासिल करने और कक्षा में 70 फीसद उपस्थिति वाले अल्पसंख्यक छात्रों को फीस माफी का लाभ मिलता है।

चुघ होंगे भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन समिति बनाई है। पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी तरुण चुघ इस समिति के संयोजक होंगे। वहीं, चांदनी चौक के सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के नेतृत्व में अनुभवी नेता घोषणा पत्र तैयार करेंगे। चुनाव की तैयारी व प्रचार अभियान को ध्यान में रखकर कुल 35 विभाग बनाए गए हैं। प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख होगा।

रचनात्मक तरीके से चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए राज्यसभा सदस्य विजय गोयल की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है। यह टीम सोशल मीडिया के लिए वीडियो व ऑडियो सहित होर्डिंग तैयार करेगी। टीम में तेजिंदर बग्गा, आतिफ रशीद, राजकुमार भाटिया, प्रत्यूष कंठ, वरुण छाबड़ा, सुनील यादव आदि शामिल हैं। सांसद हंसराज हंस और गौतम गंभीर की देखरेख में समाज के अलग-अलग वर्गों में संपर्क अभियान चलेगा। इस टीम में सूरज प्रकाश खत्री, भोलानाथ विज, रजनीश गोयनका, केएस दुग्गल व सुधीर गुप्ता को शामिल किया गया है। हर्ष मल्होत्रा को बूथ स्तर पर चुनावी कार्य का प्रभारी और धर्मवीर सिंह को प्रमुख बनाया गया है।

वैशाली से मोहननगर तक कॉरिडोर बनने पर दौड़ेगी स्वचालित मेट्रो

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

वैशाली से मोहननगर तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर पर स्वचालित ट्रेन दौड़ेगी। कंट्रोल रूम से संचालन किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने गुरुवार को इस कॉरिडोर की संशोधित डीपीआर की मुख्य विशेषताओं की कॉपी जीडीए को सौंपी। उसमें बताया कि वर्ष 2020 में निर्माण शुरू होने पर वर्ष 2025 तक कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा सकता है। यह कॉरिडोर मेट्रो की यमुना बैंक से वैशाली तक ब्लू लाइन का विस्तार होगा।

संशोधित डीपीआर के मुताबिक वैशाली से मोहननगर तक 5.04 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके निर्माण में 1808.22 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस कॉरिडोर पर प्रहलादगढ़ी, वसुंधरा सेक्टर-14, साहिबाबाद और मोहननगर पर स्टेशन बनेंगे। साहिबाबाद स्टेशन पर इसे दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इससे यात्री दोनों रेल सेवाओं का लाभ ले सकें। पहले इस कॉरिडोर को साहिबाबाद तक बनाया जा रहा था। तब इसकी लंबाई 4.16 किलोमीटर थी। लागत 1438 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

फैक्ट फाइल

- कॉरिडोर पर आठ कोच की मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी
- एक ट्रेन में 2352 यात्रियों को सवार करने की क्षमता होगी
- ट्रेन की न्यूनतम गति 33 और अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी
- केंद्र सरकार लागत में 20 प्रतिशत का अंशदान देगी
- वैशाली से मोहननगर तक 79134 .5 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा कॉरिडोर

डीएमआरसी ने वैशाली से मोहननगर तक मेट्रो कॉरिडोर की संशोधित डीपीआर की मुख्य विशेषताओं की कॉपी सौंपी है। इस कॉरिडोर के निर्माण में पांच साल का वक्त लगेगा। पूरी तरह ऑटोमैटिक मेट्रो ट्रेन ट्रैक पर उतारी जाएगी। उसमें ड्राइवर नहीं होगा।

-विवेकानंद सिंह, मुख्य अभियंता, जीडीए।

ऑटोमैटिक टिकटिंग सिस्टम लगेगा : वैशाली से मोहननगर तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर में ऑटोमैटिक टिकटिंग सिस्टम लगेगा। संशोधित डीपीआर में जिक्र है कि स्मार्ट कार्ड, मोबाइल एप से ही टिकटिंग सुविधा दी जाएगी। 2025 में टोकन व्यवस्था लगभग खत्म कर हो जाएगी।

घर के बाहर ही नहीं अंदर भी असुरक्षित है आधी आबादी

लोकेश चौहान, नई दिल्ली : महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के दावों के बीच दिल्ली की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। राजधानी में घर के अंदर ही आबादी के उत्पीड़न में इस साल वृद्धि हुई है। थाने पहुंचे मामलों को ही देखा जाए तो अब इसमें 17 फीसद की वृद्धि दर्ज हुई है। इसमें महिलाओं के साथ मारपीट व मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।

राजधानी के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए ससुराल में महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामलों में सबसे अधिक मामले पति द्वारा मारपीट किए जाने के थे। इसके बाद पति और ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के मामले में भी सामने आए। 15 नवंबर 2019 तक थानों में दर्ज मामलों की संख्या 3187 थी, जबकि 15 नवंबर 2018 तक विभिन्न थानों में 2716 मामले दर्ज किए गए थे। पूरे वर्ष की बात की जाए, तो 2018 में 3416 मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे में नवंबर और दिसंबर के डेढ़ माह में ही राजधानी में ससुराल में महिलाओं के साथ हिंसा के 700 मामले दर्ज किए गए थे। ये वे मामले हैं, जो पुलिस थाने में दर्ज किए गए हैं, जबकि कितने ही ऐसे मामले हैं, जो दर्ज ही नहीं किए गए।

केजरीवाल बोले, पांच साल में गंदे पानी की समस्या लगभग खत्म

मावलंकर सभागार में आप के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम में अगली पंक्ति में बैठे (बाएं से) विधायक सोमनाथ भारती, कमांडो सुरेंद्र सिंह, मंत्री गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज। जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मावलंकर सभागार में नई दिल्ली लोकसभा के तहत आने वाली 10 विधानसभा सीटों के लोगों के साथ टाउनहॉल मीटिंग की। इस दौरान लक्की ड्रा के माध्यम से आठ लोगों के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। साथ ही जिन लोगों के सवाल लक्की ड्रा में नहीं निकल पाए, उनका जवाब एसएमएस से दिया जाएगा। जो लोग मीटिंग में आए थे, उनका पंजीकरण कराने के बाद ही हॉल में प्रवेश दिया गया था।

आइएनए से आए शिवेंद्र मिश्रा के गंदे पानी की आपूर्ति के सवाल का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब हम आए थे तो दिल्ली में केवल 58 फीसद पानी की आपूर्ति पाइपलाइन से होती थी, लेकिन अब यह 93 फीसद हो गई है। बाकी जगह भी पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है। हमारे सरकार में आने के दौरान 2300 स्थानों पर गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत मिली थी जो कि अब यह महज 125 रह गई है। हमारे विरोधी भी यह मुद्दा उठा चुके हैं और कहते हैं कि दिल्ली में 10 लाख लोगों के घर में वाटर प्यूरीफायर लगा है। दिल्ली में 50 लाख लोगों में 10 लाख लोगों के घर में वॉटर प्यूरीफायर लगा है तो 40 लाख लोग तो नल का ही पानी पी रहे हैं। मैं मानता हूं कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उन्हें तेजी से दूर किया जा रहा है।

पांच साल में दिल्ली को चमका देंगे : सीएम ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड रखते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे यह बताते हुए गर्व होता है कि हमारी सरकार ने इन दो मुद्दों पर बहुत ही गंभीरता से कार्य किया है। इससे अब सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम निजी स्कूलों से बेहतर हो रहे हैं।

जो रजिस्ट्री दे, उसी पर करना विश्वास : आरके पुरम की झुग्गी बस्तियों से आए संजय रॉबिंसन ने सवाल किया कि उनके मकानों को पक्का करने की बात हो रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या पक्का हुआ है। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने नवंबर 2015 में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया था। लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। दिल्ली में बिजली-पानी पर होते काम को देखते हुए अब केंद्र सरकार इन कॉलोनियों को मालिकाना हक देने की बात कह रही है। हमने आठ हजार करोड़ की राशि से कच्ची कॉलोनियों में गली से लेकर नाली बनवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मकान जब ही पक्का माना पाएगा जब उसकी रजिस्ट्री हो। इसलिए उसी पर विश्वास करना जो आपके मकानों की पक्की रजिस्ट्री दे दे। वहीं मोती नगर की मेघना साहू ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान राशि को कम करने का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इससे लोग यातायात नियमों को मानने लगे हैं, लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इस पर वह जरूर विचार करेंगे।

विधायकों के समर्थन के नारे पर सीएम ने जताई नाराजगी : मीटिंग में संवाद के दौरान कुछ लोगों ने दिल्ली कैंट से विधायक सुरेंद्र कंमाडो और आरके पुरम से प्रोमिला टोकस के समर्थन में नारे लगाए तो अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के नारे लगाना ठीक नहीं है। हम यहां देश बदलने के लिए आएं हैं, किसी को टिकट दिलाने के लिए नहीं।

आयोजन

जोधपुर का दही चिकन, उड़ीसा के छेन्नापोडो, मुंबई की पुरनपोली और दिल्ली के लजीज स्ट्रीट फूड का लें स्वाद

जेएलएन में 26 राज्यों के स्ट्रीट फूड का उठाएं लुत्फ

रितु राणा, नई दिल्ली

जोधपुर का दही चिकन, उड़ीसा के छेन्नापोडो, मुंबई की पुरनपोली और दिल्ली के लजीज स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना है तो पहुंच जाइए जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम। जेएलएन स्टेडियम में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) की ओर से पांच दिवसीय 11वें राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी में पड़ रही कड़ाके की ठंड में दिल्ली के साथ-साथ यहां उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिमी भारत समेत 26 राज्यों के स्ट्रीट फूड का लुफ्त मिलेगा। नासवी की ओर से आयोजित इस फेस्टिवल का उद्देश्य देश के हर कोने के स्ट्रीट वेंडर्स को एक स्थान पर लाकर सम्मान दिलाना है।

जेएलएन में आयोजित यह फूड फेस्टिवल 29 दिसंबर तक चलेगा। इसकी एंट्री फीस 100 रुपये है। यहां आपको उचित दामों में देश के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यजंनों का स्वाद मिल जाएगा। दिल्ली के मयूर विहार इलाके की प्रसिद्ध राज कचोड़ी, चांदनी चौक की दौलत की चाट, लक्ष्मी नगर की स्पेशल अमृतसरी नान खाकर आपको मजा जा जाएगा। वहीं, नॉन वेज में जामिया नगर बाटला हॉउस का चिकन तंदूरी, चिकन मलाई टिक्का, चिकन सीख कबाब का स्वाद लाजवाब है। लक्ष्मी नगर के कौशल अलवी के चिकन शामी कबाब, चिकन बिरयानी, मटन शामी कबाब व कोरमा का भी कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा यहां लोग लक्ष्मी नगर के अमृत स्पायरल पटैटो खूब पसंद कर रहे हैं। यहां एक स्टिक में फ्राइड पटैटो चिप्स को स्पायरल करके परोसा जा रहा है, जिसका स्वाद लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

द्वारका के पिज्जा ऑमलेट स्टॉल पर पहुंचते ही लोगों की नजरें वहीं थम जाती हैं। यहां आपको स्वादिष्ट पिज्जा ऑमलेट मिलेगा, जिसे पैन में फ्राइ करके उससे आग निकालकर पकाया जाता है। इस तरह से पिज्जा ऑमलेट बनाने के तरीके को देखकर लोग खूब आकर्षित हो रहे हैं। वहीं, इंडिया गेट के इस्माइल के फायर वाले पान का भी लोग खूब लुत्फ ले रहे हैं। करोल बाग के अफगानी मोमो, अचारी मोमो व चॉकलेट मोमो का स्वाद भी लाजवाब है।

विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का लें स्वाद

बिहार के पनीर लिट्टी व चिकन लिट्टी, उत्तराखंड के प्रसिद्ध मनडुव की रोटी व मनडुव का हलवा, लखनऊ की प्रसिद्ध कुल्फी, अयोध्या की कुल्हड़ जलेबी व खुरचन पेड़ा। पंजाब की खास गुड़ की चाय, मुंबई का मिस्कल पाव, जुनाका भाकर, पुरनपोली व कड़ी समोसा, मध्य प्रदेश का इंदौरी पोहा भी हैं खास। वहीं, नॉन वेज में उड़ीसा का माछ भात व माछ तरकारी भात, मोतीहारी का मीट भात, कर्नाटक का चिकन 65, पुडुचेरी का चिकन पेरी का स्वाद भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

खाने के साथ गीत-संगीत का भी लें आनंद

स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में बच्चों के मनोरंजन के लिए किड्स एक्टिविटी जोन बनाया ग